Wilson Center | Digital Archive
International History Declassified
digitalarchive.wilsoncenter.org

July 25, 1968
Rajya Sabha Extended Debate on the Non-Proliferation Treaty Draft

Citation:

"Rajya Sabha Extended Debate on the Non-Proliferation Treaty Draft", July 25, 1968, Wilson Center Digital Archive, Institute for Defence Studies and ANalyses (ISDA), Rajya Sabha Q&A Documents. https://digitalarchive.umd.edu/document/119765

Summary:

Transcript of debate between members of the Rajya Sabha and the Minister of State in the Ministry if External Affairs, Shri B. R. Bhagat, on the Non-Proliferation Treaty and why India has chose not to sign.

Credits:

This document was made possible with support from Carnegie Corporation of New York (CCNY)

Original Language:

Hindi

Contents:

- Original Scan

Wilson Center Digital Archive Original Scan

मानवीय आधार के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, किसी भी सभ्य व्यवहार के अनुसार, जैसा कि किसी भी देश को करना चाहिये, पाकिस्तान को भी उन्हें रिलीज़ करना चाहिये। चूंकि वह अपनी पूरी मीयाद भुगत चुके इसलिये अपील का सवाल नहीं उठना चाहिये इसलिये हम कोशिश कर रहे हैं कि वह उनको जल्द से जल्द छोड़ दें। वह कहते हैं उनके बदले में हम किसी को दें। वह भी हम विचार कर रहे हैं. . .

श्री राजनारायण : उनके बदले में मंत्री जी खुद चले जायं।

श्री सैयद अहमद : राजनारायण को भेज दीजिए।

SHRI S. S. MARISWAMY : Sir, I would like to know whether any officials of the High Commissioner's office had made any attempt to meet this boy.

SHRI B. R. BHAGAT : Yes.

SHRI S. S. MARISWAMY : Would the hon. Minister give us the details of how he met him and what was the conversation that took place? Could he give us some details ?

SHRI B. R. BHAGAT : When the two officers of the Indian Mission in Pakistan visited the Bahawalpur jail, they were told by the boy that he was sentenced to two years' imprisonment and he was due for release on the 10th of April, 1968.

SHRI S. S. MARISWAMY : Subsequent to this did the official contact the highest authorities in Pakistan for the immediate release of the boy ?

SHRI B. R. BHAGAT : Yes, not once, not twice but in the last two years we have been making repeated efforts for the release of the boy.

श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के पाकिस्तान स्थित उच्चायुक्त का यह कर्तव्य नहीं है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी गर्दिश में वहां फंसे तो उसकी खबर लें और इस मामले में भारत के उच्चायुक्त को कब ख़बर हुई और ख़बर नहीं हुई तो क्यों नहीं ख़बर हुई और माननीय मंत्री का यह कहना कि चूंकि उसकी मीयाद खत्म हो गई है इसलिये हम अपील नहीं कर सकते, इसके बारे में मेरा कहना है कि कभी मीयाद खत्म होने पर भी अपील की जाती है और इसमें ऊंचे इजलासों का फैसला होता है कि इस आदमी ने कोई जुर्म किया या नहीं किया। तो मैं जानना चाहता हूं कौन कौन सी कार्यवाही भारत के उच्चायुक्त ने की या भारत सरकार ने की और इस लड़के के बारे में उनको कब खबर हुई ?

श्री बी० आर० भगत : जैसा कि जवाब में मैंने पहले बताया वह लड़का कहां था, इसका पता उस लड़के के पिता को भी नहीं था। पाकिस्तान के अधिकारियों ने उस पर चार्ज लगाया और चुपके चुपके उसको जेल में बंद कर दिया। आम तौर से इन बातों की ख़बर डिप्लोमेटिक स्तर पर दी जाती है। अगर वह न दें तो कोई और ज़रिया तो है नहीं कि हम जान पाएं। मगर जैसे ही बाद में हमको ख़बर उसके पिता के द्वारा लगी तो हमने सब कोशिश की उसको वापस लाने की और यह बात सही है कि संभवत: कानूनी स्थिति है कि हम हाईकोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते, मगर मालूम नहीं ऐसा वहां सम्भव है कि नहीं। लेकिन कानून के हिसाब से अगर इस मामले को लेंगे तो उसमें लम्बी देर लगेगी। यह भी मीयाद भुगत चुके हैं। मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द उनको वापस लाया जाय। यही हमारी मांग है, यही उचित भी है और इसी का प्रयास है।

*92 [*Transferred to the 6th August,* 1968]

NUCLEAR NON-PROLIFERATION TREATY

*93. PROF. SHANTILAL KOTHARI†:
SHRI R. P. KHAITAN :
SHRI M. N. KAUL :
SHRI JAGAT NARAIN :
SARDAR RAM SINGH :
DR. (MRS.) MANGLADEVI TALWAR :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India have told the United Nations

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Prof. Shantilal Kothari.

Wilson Center Digital Archive Original Scan

that India would not subscribe to the draft nuclear non-proliferation treaty;

(b) if so, what is the reaction of the world countries to our stand in the matter;

(c) whether the Government of India have received any communication from the United States and the Soviet Union in this matter ;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) whether India has given suggestions for revision of the treaty and if so, in what way?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) Yes, Sir. The Indian Delegate expressed our views concerning the Treaty at the last session of the General Assembly.

(b) The General Assembly adopted a resolution commending the Treaty by a vote of 95 in favour and 4 against. India abstained from voting on the resolution together with 20 other countries. Other countries have shown understanding of India's position, even though all may not have agreed with it.

(c) None on this subject since the adoption of the Treaty.

(d) Does not arise.

(e) India's view was that the Treaty should be revised to conform fully to the United Nations General Assembly Resolutions 2028(XX) and 2153.A(XXI).

श्री जगत नारायण : मैं वजीर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि इस ट्रीट्री में कौन कौन से देश मामिल हुए हैं और कौन कौन से देश शामिल नहीं हुए हैं और हिन्दुस्तान ने जो इस ट्रीट्री में शामिल न होने का फैसला किया है इसकी क्या वजह है, क्यों वह शामिल नहीं हो रहा है, ज़रा तफसील से बताया जाय ?

श्री बी० आर० भगत : जो 95 देश शामिल हैं उनकी फैहरिस्त मैं रख दूंगा। पूरी लिस्ट लम्बी है उन 95 देशों की जिन्होंने ट्रीट्री के हक़ में कहा है। जहां तक भारत का सवाल है, हमारा यह विचार है कि इसके जो राजनैतिक और आर्थिक पहलू हैं वे इस प्रकार के हैं कि एक देश और दूसरे देश में डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है, सब को बराबर से नहीं देखा गया है। यदि हम चाहते हैं कि क्या उपाय किया जाय जिससे नान-प्रालिफरेशन ट्रीटी कारगर हो और ऐसी हो जो सब को मान्य हो तो ये अणु और परमाणु हथियार जो हैं यह उन देशों के लिये जिनके पास हैं और जिनके पास नहीं हैं, सभी के लिये बनाना या उसका स्टाकपाइलिंग बंद करना होगा। इसलिये जो जिम्मेदारी है, आब्लिगेशन और रेस्पांसिबिलिटीज़ जो हैं वह सभी देशों पर बराबर की होनी चाहियें, ऐसा नहीं कि जिन देशों के पास आणविक अस्त्र नहीं हैं उनके ऊपर ज्यादा आब्लिगेशन्स और रेस्पांसिबिलिटीज़ हों और जिन देशों के पास हैं उनकी कुछ न हो; तो बैलेन्स आफ रेस्पांसिबिलिटी और आब्लिगशन हो। इसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे रोकथाम या रुकावटें क्या हों। हम सब जानते हैं कि भारत अणुशक्ति का प्रयोग अपने औद्योगिक या कृषि या दूसरे आर्थिक निर्माण के कामों के लिये कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से, और इसमें भी अगर रुकावटें आएं या इसमें भी हमारी स्वतंत्रता को धक्का लगे तो उसका खयाल हमको करना होगा। इन सब कारणों से हमने यह सोचा कि हमारे राष्ट्रीय हित में नही है कि हम लोग इस संधि पर हस्ताक्षर करें।

श्री जगत नारायण : क्या चीन को भी इस ट्रीट्री पर दस्तखत करने की दावत दी गई थी ?

श्री बी० आर० भगत : चीन इस ट्रीट्री में शामिल नहीं हो रहा है और चीन है भी नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ मे।

DR. (MRS.) MANGLADEVI TALWAR : One of the reasons why India has not signed the Treaty is that India wishes to reserve the right to manufacture atomic appliances for peaceful purposes. That is a very good thing. But at the same time it has been reported from different sources that manufacture of atomic weapons is going at full speed is ahead in China How does the Government of India think of meeting this threat to safeguard our sovereignty and the safety of the people ?

Wilson Center Digital Archive Original Scan

SHRI B. R. BHAGAT : On this matter our position is very well known that we have repeatedly said that we will not manufacture atomic weapons. At the same time it is also true that we are for a real credible security guarantee for all countries and it will be our effort that for all and particularly those countries that have opted not to go in for atomic weapons we should be able to secure credible genuine security guarantee against any nuclear threat either from China or any other country.

(*Many hon. Members got up*)

MR. CHAIRMAN : A number of Congressmen have already asked questions. I must see that I give chance to others also. You can trust on my wisdom to see that justice is done to all.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : संधि के प्रारूप पर हमने आपत्तियां उठाई थीं परन्तु उसके बावजूद भी वह संधि स्वीकार की जा चुकी है। जिस रूप में वह स्वीकृति हुई है, क्या हम उसके संबंध में अपनी नीति बना रहे हैं? अगर उस संधि का जो आज प्रारूप तैयार हुआ है, यद्यपि उसमें निशस्त्रीकरण वार्ता चलाने की व्यवस्था है। परन्तु चीन एक ऐसा देश है जिस के पास अणु-शस्त्र है और चीन के साथ वार्ता चलाने की बात सम्भावना होते हुए भी, उस संधि के माध्यम से, इस बारे में सफलता की विशेष गुंजायश नजर नहीं आती है। अर्थात् हर प्रकार से यह संधि हमारे हितों के विपरीत है। हमारे लिए अणु संकट में किसी भी प्रकार से कमी आने वाली स्थिति इसने पैदा नहीं की है। ऐसी उत्पन्न परिस्थिति पर, जबकि संधि पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और हमारे विरोध की चिन्ता न करते हुए भी, अब सरकार इस संकट से उत्पन्न परिस्थिति पर अपनी नीति किस प्रकार से निर्धारित करना चाहती है?

श्री बी० आर० भगत : संधि से तो कोई संकट पैदा नहीं हुआ है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : संकट रुका भी नहीं है।

श्री बी० आर० भगत : यह भी बात है। इस संधि को 95 देशों ने मंजूर किया है और जो बाकी देश हैं वे तो या चुपचाप रहे, या उन्होंने इसका विरोध किया। अब सवाल यह है कि इस अणु-शक्ति के प्रहार का जो संकट आजकल हमारे ऊपर है, उसका निदान क्या है और उस संकट को टाला कैसे जा सकता है। इस संबंध में हमारी नीति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है और फिर हम जब तक कम्पलीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और जनरल डिसआर्मामेंट नहीं करते तब तक इस संकट को टाला नहीं जा सकता है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : इसको बढ़ाने का रास्ता क्या है?

श्री बी० आर० भगत : इसको बढ़ाने का रास्ता यही है कि सभी देश जो हैं, वे इसको मानें। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग है इसलिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। उसके ऊपर कोई बंदिश हो क्योंकि उसकी नीति अब भी ऐसी है कि वह अणु का प्रयोग कर सकता है। मगर जब सभी देश, दुनिया के बड़े बड़े देश, जो बड़े शक्तिशाली हैं, अणु और परमाणु शक्तियों से सम्पन्न हैं अगर वे और दुनिया के दूसरे सभी देश न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ सही कदम बढ़ायें और आगे बढ़ें तब इस संकट को टाला जा सकता है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जानसन और प्रीमियर कोसीजिन ने इस तरफ कदम भी उठाये हैं जो कि एक सही कदम है और जिसका हमने स्वागत किया है। तो मैं समझता हूं कि रास्ता यह है और इसके लिए हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिये। हमें दुनिया के अन्दर ऐसा वातावरण बनाना चाहिये कि अगर चीन किसी भी प्रकार से इन हथियारों का प्रयोग करना चाहेगा, किसी पर प्रहार करना चाहेगा, तो वह सारी दुनिया की शक्तियों के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकेगा।

SHRI C. D. PANDE : It is a matter of great gratification that the Government of India has taken a veay correct stand in

Wilson Center Digital Archive Original Scan

this respect and it has been taken in consonance with the feelings in this country because the country feels that it is preposterous that however powerful two nations may be, they should take upon themselves the protection of the world and deny the right of manufacture of bombs by other nations. Apart from this, may I know whether the Government of India has made such a clear indication of their policy in this regard? What was the motive and what was the expediency and what was the point in abstaining from voting in regard to this Treaty? The idea that we abstained shows that we have watered down our opposition.

SHRI B. R. BHAGAT : Our abstaining in the U. N. parlance does not mean watering down our stand in any way the strength of our viewpoint. It only means that we do not subscribe to the principles underlying this Treaty and that is to be emphasised. Whatever effort they are making, we are not opposed to that effort. We only say that this does not go far enough. They are not adequate. That is the reason.

MR. CHAIRMAN : Shri Rajnarain.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि **जिन संकटों** से यह संधि पैदा हुई वे संकट क्या क्या हैं और इस संधि से इन संकटों का निराकरण होगा या नहीं ?

श्री बी० आर० भगत : असल में संकट तो दुनिया पर परमाणु बमों के प्रयोग का खतरा है।

श्री राजनारायण : क्या मंत्री महोदय ने हमारे सवाल को समझ लिया है ?

श्री बी० आर० भगत : आप जवाब समझें। आपके सवाल को हमने समझ लिया है। जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि संधि में जिन बातों का जिक्र हुआ और जो संधि का मसवदा है, उससे हम यह समझते हैं कि वह पूरा नहीं है।

श्री राजनारायण : क्या संकट है ?

श्री बी० आर० भगत : संकट के बारे में तो मैंने बतला दिया है और अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि संकट तो परमाणु बम और अणु शक्ति के प्रयोग का खतरा है। यह खतरा आज हमारे सामने है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, अगर आप इस उत्तर को समझ गये हों, तो मैं भी समझ लूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन संकटों के निवारण के हेतु यह परमाणु बम प्रसार निषेद संधि हुई है ? क्या यह सरकार उन संकटों के बारे में जानकारी रखती है ? यदि हां, तो क्या इस संधि मात्र से इन संकटों का निराकरण किया जा सकता है ? क्योंकि हमारे माननीय भगत जी एक भले और सीधे सादे आदमी हैं। मगर उनके उत्तर को समझकर मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि सरकार के पास क्या संकट है, उसकी जानकारी उसके पास नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मूल भूत रूप से उस संकट को जान पा रही है जिसके निराकरण के हेतु परमाणु बम प्रसार निषेध संधि हुई है ?

श्री बी० आर० भगत : यह तो मैटाफिजिक्स का सवाल पूछा गया है। संकट का जिक्र तो हमारे माननीय भंडारी जी ने किया था और उसका जवाब दिया जा चुका है। अब आप किस संकट की चर्चा करना चाहते है? अगर माननीय सदस्य बतलायें तो मै उस संबंध में प्रकाश डालूंगा।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, पार्लियामेंटरी प्रोसेस में एक सदस्य से भी सवाल किया जा सकता है। पार्लियामेंटरी प्रोसेस के नियम के अनुसार सदस्य से सवाल पूछा जा सकता है अगर सरकार जानना चाहती है। आप मुझे मौका दें कि मै सदन को इस संबंध में बतला दूं। आज विश्व में संकट है। देश देश में विषमता है, मुल्क मुल्क में विषमता है, मनुष्य मनुष्य में विषमता है। अगर यह मान लिया जाय कि परमाणु बम न रहे तो युद्ध होगा या नहीं ? अगर परमाणु बम न भी रहेंगे तो भी युद्ध होगा और पुराने हथियारों से होगा। यह जो शुद्ध संकट विषमता का है वह विश्व और भारतवर्ष में भी फैला हुआ है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस असमानता के संकट को समाप्त करने के लिए इस सरकार ने अबतक क्या कदम उठाये हैं। मनुष्य मनुष्य

Wilson Center Digital Archive Original Scan

के अन्दर असमानता को दूर करने के लिए, मुल्कों के अन्दर असमानता को दूर करने के लिए और सारे विश्व में समान आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कायम हो, इन सब कामों के करने से ही यह संकट टाला जा सकता है। यह हमारा सवाल है।

SHRI A. P. CHATTERJEE : Mr. Chairman, Sir, will the hon. Minister make matters clear? In view of the fact that the Nuclear Non-Proliferation Treaty really amounts to nuclear monopoly for some super States, in view of that it won't do merely to say that the super powers will not manufacture more nuclear weapons, because the nuclear weapons already in stock are enough to destroy the whole world. Now, in view of that fact, did the Indian Government emphasise before the super States of the United States of America and the U.S.S.R. that they should not use nuclear weapons in any future conflict and, secondly, ask whether they are prepared to destroy the huge stock piles of atomic weapons in their possession? If they have not emphasised that, they have not emphasised the real thing. I want to know from the Minister whether they emphasised before the super States these two points.

SHRI B. R. BHAGAT : Sir, as I have said, we have emphasised total nuclear disarmament, and general disarmament also. At the moment, as the situation stands, even the limitation on the manufacture of nuclear bombs has not been agreed to, not even in this Treaty. That is one of the objections. Secondly, the declaration the two powers have made is a step in that direction; though a small step it is a step in the right direction and it says: "The question of limitation and reduction of both offensive strategic nuclear weapons and delivery system as well as the system of defence against ballistic missiles." So this is the step of this declaration which they are going to discuss—limitation and reduction—so that it is a step in that direction.

SHRI A. P. CHATTERJEE : Where is the guarantee for non-use?

SHRI R. T. PARTHASARATHY: May I know from the Minister whether a number of Members of the United Nations, particularly the smaller nations, have conveyed their appreciation of the stand that India had taken with reference to non-subscription to the Draft Nuclear Non-Proliferation Treaty and, if so, what further steps the Government of India proposes to take to propagate their view the ultimate view of compelling the great nuclear powers to rescind from singing such a Treaty?

SHRI B. R. BHAGAT : Sir, it is true that some of the countries have appreciated the stand that we have taken. The very fact that we, whether at the meeting of the 18 nations or in the General Assembly debate, have made our position known in very precise terms, although not giving the impression that we are trying to create a lobby against this Treaty—we do not want to do that—but the very fact that we have put our viewpoint very clearly and taken our stand precisely is very much understood, and in all future deliberations and in all such meetings, we will continue to pursue our objectives.

SHRI ARJUN ARORA : May I know if the Government of India's non-signing of this Non-Proliferation Treaty had any thing to do with what has come to be known as the nuclear umbrella? I ask this question because something said by Prime Minister Wilson of Great Britain recently in the House of Commons gave the impression that the Government of India have not signed this Treaty because there has been no agreement on the nuclear umbrella, and he said that he was trying to negotiate. May I know, Sir, if there is any truth in what Mr. Harold Wilson, Prime Minister of Great Britain, has said, about the unclear umbrella being responsible for the Government of India's not signing this Nuclear Non-Proliferation Treaty?

SHRIMATI INDIRA GANDHI : No, Sir.

डा० भाई महावीर : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस संधि पर हस्ताक्षर न कर के जो एक स्वाभिमान का पग उठाया गया है क्या सरकार यह समझती है कि हस्ताक्षर न करना अपने आप में कोई ऐसा शस्त्र है या परमाणु के आक्रमण के विरुद्ध किसी प्रकार का आरक्षण उसके अन्दर निहित है अथवा सरकार ने यह भी सोचा है कि जिस समय इस प्रकार का खतरा उपस्थित होगा तो उस खतरे का सामना करने के लिये हमने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये, इस प्रकार का डाक्यूमेंट हम केवल आक्रमक के सामने प्रस्तुत करके अपनी रक्षा कर सकेंगे ? यह मैं इस लिये कहता हूं कि कल जो चर्चा

Wilson Center Digital Archive Original Scan

रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र देने के विषय पर हुई तो बार बार उसके सम्बन्ध में सब सदस्यों ने कहा और माननीय प्रधान मंत्री ने भी कहा कि हमें सेल्फ रिलायन्ट होना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर होना पडेगा और आत्मनिर्भरता की कसौटी पर हमारा इस संधि पर हस्ताक्षर न करना मात्र क्या कोई बड़ा भारी पग है। यदि नहीं, तो क्या सरकार परमाणु बम के सम्बन्ध में अपनी जो अब तक की नीति है उसमें पुर्नविचार करने का इरादा रखती है।

श्री बी० आर० भगत : श्रीमन्, जहां तक परमाणु बम के बनाने की बात है उसमें हमारी नीति स्पष्ट है और हम क्यों नहीं बनाना चाहते इसके कारण भी हमने दिये हैं। संधि पर हस्ताक्षर न करना मात्र, यह हम नहीं मानते कि इससे ही हमारे सब संकट टल जायेंगे या जो भी समस्याएं हैं परमाणु बम से निहित वे सब सुलझ जायेंगी। जिन कारणों को ले कर हमने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये वे हमने अभी बताये हैं और जो खतरा है परमाणु शक्ति के प्रयोग का हम पर या जो दुनिया को खतरा है और परमाणु शक्ति से जो खतरा हो सकता है उसके निवारण के लिये हमारी नीति स्पष्ट है और हम उसकी तरफ प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे।

SHRI KRISHAN KANT : In view of the very clear stand the Government of India has taken regarding this Treaty, do I take it that we have the option of going in for nuclear development in our own country? May I know from the hon. Minister if for the development of nuclear technology and development of research in the country peaceful explosion of nuclear devices is required will our nuclear scientists be free to do that?

SHRI B. R. BHAGAT : It is a hypothetical question. We will cross the bridge when we come to it.

SHRI KRISHAN KANT : No, no, I am asking whether for the peaceful development of nuclear technology, if supposing we want to have a new tunnel—can we not require?—if for the development of that we required peaceful explosion of a nuclear device, shall our nuclear scientists be free to do that?

MR. CHAIRMAN : All these matters are before them.

SHRI BHUPESH GUPTA : The only thing I would like to ask is whether we have the assurance that Government will not try to build up a lobby. I think the Government's position is correct in this matter. Whereas they have signified their inability to sign this treaty they are not at the same time trying to propagate in favour of the Indian case or position. It is the correct position, but I should like to know whether the Government has taken into account that some of the statements made by the leaders of the Government here partly to placate the atom-bomb lobby in this country is creating an impression that despite the fact that India is a signatory to the Moscow Partial Test Ban Treaty India is considering the production of nuclear weapons. Now I should like to know what steps our diplomatic missions abroad are taking in order to counter that impression which puts the Indian position in the wrong line. For domestic consumption they say something here but this is reported in the foreign papers and people get the impression as if the Indian Government is keeping this question open and they may poduce a nuclear weapon.

SHRI B. K. P. SINHA : Why not ?

SHRI B. R. BHAGAT : I do not know, Sir, which statement by which leader of the Government the hon. Member refers to. On this question our position is very clear. We have said that we do not intend to manufacture atomic weapons, and this position is known to all the countries concerned. Our missions abroad know that this is our stand, but I know this that our not signing this Treaty may be misconstrued by some countries who are opposed to us and they may say that we want to keep the option to go in for the atom bomb and so are keeping the question open. This may be but . . .

SHRI BHUPESH GUPTA : Not "may be"; I do not know your Foreign Affairs Ministry but it is "is".

SHRI B. R. BHAGAT : Well, we have anticipated it and we have tried to put the picture straight and asked all our missions to clearly put forward our position and state clearly what our stand on this important question is.

Wilson Center Digital Archive Original Scan

SHRI M. M. DHARIA: Mr. Chairman, Sir, we are happy that the Government has taken a clear cut stand on this matter but if we want to make this stand more effective is it not necessary to create our own lobby particularly when nearly 20 countries have not signed and are not party to this treaty? Why should we not have our own consultation with those countries and why should we not create an atmosphere in the whole world? And why should we not have a lobby of our own for that purpose? (*Interruptions*)

SHRI B. R. BHAGAT: That very word itself smacks rather of partisanship. I think the very fact that we have not tried to build up a lobby and propagate against it but confined ourselves to stating our position precisely and clearly has evoked wider appreciation than what any lobby could have done.

MR. CHAIRMAN: Question No. 94.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, एक निवेदन हैं, वह 94 जो क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। 109 जरा देख लिया जाय तो 109 और 94 इन दोनों को एक साथ ले लिया जाय तो क्या हर्ज है?

श्री ए० जी० कुलकर्णी : पहले आप बोलें तो सब ठीक हो जाय।

SHRI BHUPESH GUPTA: One advantage of it is my friend, Mr. Rajnarain, can immediately ask supplementaries.

श्री० ए० जी० कुलकर्णी : पहले आप को पूछने दिया जाय तो सब ठीक हो जाता है।

MR. CHAIRMAN: All right; agreed.

SHRI BANKA BEHARY DAS: I entirely agree with this decision but you must remember on other occasions you have said that you would not agree . . .

MR. CHAIRMAN: I am certain I have never said that. Certainly I shall have to use my discretion.

श्री राजनारायण : बांके बिहारी जी गलत हैं। आपने कभी ऐसा नहीं कहा।

MR. CHAIRMAN: Question Nos. 94 and 109 shall be taken together.

श्री राजनारायण : अगर क्वेश्चन समान है तो आपने बराबर अनुमति दी है। हां असमान क्वेश्चन को कोई समान बताए तो आप अनुमति नहीं देते।

SUPPLY OF TANKS TO PAKISTAN

*94. SHRI SITARAM JAIPURIA: †
SHRI R. P. KHAITAN:
SHRI N. SRI RAMA REDDY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply to Starred Question No. 93 given in the Rajya Sabha on the 2nd May, 1968 and state:

(a) whether Government have received any reply from the Governments of U. S. A. and Italy to the protest notes regarding supply of the American Tanks to Pakistan through Italy;

(b) if so, the nature of the replies received;

(c) what is the reaction of the Government of India of these replies;

(d) whether Government have received any further information from our mission in U. S. A. and Italy after 2nd May, about the number of tanks supplied to Pakistan and if so, what is the number of tanks?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) to (c) As stated in the House on May 2, 1968, India's concern and anxiety regarding the reported deal for the supply by Italy to Pakistan of U.S. made Patton tanks has been conveyed to the Governments of United States and Italy. The Government continued to pursue the matter through diplomatic channels. According to the latest information, no agreement has been signed by Italy with Pakistan for the sale of the tanks.

(d) Does not arise.

SUPPLY OF AMERICAN TANKS TO PAKISTAN

*109 SHRI RAJNARAIN‡:
SHRI P. C. MITRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan is trying to get American tanks through Belgium and other countries after the supply of the same through Italy was refused; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sitaram Jaipuria.

‡The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Narain.